>

Title: Need to provide special economic package to the farmers of drought affected regions of Maharashtra.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): इस साल मानसून बारिस नहीं हुई है । यह माना जाता है कि जब बारिस 10 फीसदी कम होती है तो उसका असर देश की 20 से 40 फीसदी खेती पर पड़ता है और सूखे की सुबगुहाट मिलती है । इस साल हम इस स्थिति से बहुत आगे निकल चुके हैं । सूखे की स्थिति की सबसे बड़ी मार पशुओं पर पड़ती है । इसका मतलब मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि मवेशियों के चारा और पानी की व्यवस्था करने की चुनौती भी सिर पर है । कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए डीजल और बीजों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है । लेकिन सरकार यह भूल रही है कि योजना बनाने में और उसे किसानों तक पहूंचने में जितना वक्त लगेगा उसके बाद उन बीजों की बुआई की हालत भी नहीं रहेगी । महाराष्ट्र राज्य के सूखे प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन और राहत कार्य की चुनौती खड़ी कर दी है वही महंगाई से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी किसान तथा मवेशियां सूखे की मार झेल रहे हैं । इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को तुंत कार्यवाही हेतु स्पेशल पैकेज दिया जाये ।